



प्रेस विज्ञप्ति

12.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत आईडीबीआई बैंक द्वारा दायर आवेदन के समर्थन में, मेसर्स एक्सेल सनशाइन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जब्त की गई 54.86 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को आईडीबीआई बैंक को वापस कर दिया।

ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफसी, बेंगलूर द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो आईडीबीआई बैंक द्वारा मेसर्स एक्सेल सनशाइन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आईडीबीआई बैंक को शुरुआत में शिवा समूह की कंपनी विन विंड ओय को दिए गए 52 मिलियन यूरो के ऋण से भारी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का नुकसान हुआ था; वसूली की कार्रवाई जारी रहने के दौरान, आईडीबीआई के अधिकारियों और शिवा समूह ने कथित तौर पर मार्च 2014 में शिवा समूह से जुड़ी एक अन्य इकाई, एक्सेल सनशाइन लिमिटेड के लिए 83 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नया ऋण सुरक्षित करने के लिए साजिश रची; इस नए ऋण का एक बड़ा हिस्सा (65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) कथित तौर पर विन विंड ओय के एनपीए को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे शिवा समूह को लाभ हुआ। नियामकीय उल्लंघनों, प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी और संपात्ति/गारंटी के जानबूझकर दुरुपयोग के बावजूद ऋण स्वीकृत किया गया था; और इस तरह से एनपीए को बंद करके, आईडीबीआई बैंक ने कथित तौर पर सभी वसूली कार्रवाइयों को वापस ले लिया और एसआईएचएल की कॉर्पोरेट गारंटी जारी कर दी, जिससे 600 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ।

पीएमएलए जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने ऋण का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए करने के बजाय, बैंक की धनराशि को व्यवस्थित रूप से अनपेक्षित उद्देश्यों के भुगतान के लिए डायवर्ट किया और उसका दुरुपयोग किया। ईडी ने दो अस्थायी कुर्की आदेशों के माध्यम से लगभग 245 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया, जिसकी पुष्टि बाद में न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा 13.01.2020 और 24.11.2025 को की गई। ईडी ने 22.02.2021 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की।

आईडीबीआई बैंक ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत दो अचल संपत्तियों की बहाली के लिए विशेष न्यायालय में याचिका दायर की। ईडी ने इस पर सहमति जताई क्योंकि कुर्की पीड़ित बैंक के हित में की गई थी। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 09.12.2025 के आदेश द्वारा जनहित को और पीड़ित बैंक के नुकसान को ध्यान में रखते हुए 54.86 करोड़ रुपये मूल्य की दो संपत्तियों को बहाल कर दिया।